

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय  
SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT OF INDIA  
नई दिल्ली - 110001 (भारत)  
NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1/आर.टी.आई./41/2025-2026

18 नवम्बर, 2025

श्री सुभाष चन्द्र,  
पता-ई-18, मनसा पार्क,  
उत्तम नगर, दिल्ली-110059

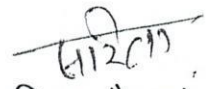
विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में आपका दिनांक 07.11.2025 का पत्र जो इस सचिवालय में 07.11.2025 को प्राप्त हुआ है, जिसके साथ 10 रुपये का पो०आ०सं० 66एफ 364408 संलग्न कर आपने अपने आवेदन पर की गई कार्रवाही की जानकारी चाही है।

इस विषय में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

  
(सरिता चौहान)  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

010  
SPEED POST  
21/11/25

प्राथम्य पत्र P-15 तारीख - 30/07-25

07-11-25

सेवा सं.  
P.O. No  
66F-364408

श्री. श्री. सुरेश कावणजी V.P.  
महामहिम V.P. House,  
गणेश सरकार नई दिल्ली

RTI-40



विषय :- जन-सूचना अधिनियम अधिनियम 2005 के

अनुसार RTI की जानकारी हिन्दी में देने के बारे में।

महाशय जी, हमने बहादुर सुधा, प्रदीप सुधा,

सुष्मा सुधा व विनायक सुधा से दिनांक 23-5-25

F No 1674 प्राथम्य पत्र दिया था (बिठाया जाये)

जैसे NDMC स्टॉप न करे के आदेश पर अन्य  
5 आदर्शों के बिठाया गया था

उसी तरह करे के आदेश होने हुए महामहिम

V.P. House गणेश सरकार न. दिल्ली ने 23-5-25

F. No 1674 प्राथम्य पत्र पर आप का आदेश  
दिया गया है। उस की आदेश की फोटो कापी

दी जाये व उस की कापी NDMC स्टॉप की भेजे  
है। उस की प्रतिलिपि हमें दी जाये। आप को

अपने पत्रबन्दी रहेगी।

इस 4 आदर्शों की आदेश की कापी दी जाये।

शुभाशु Subhash

सुभाष चंद्र

E-18 अलसा राय मार्ग, उदाय  
नगर, नई दिल्ली - 59

9211102083

द्वारा प्राधान्य में भी है और इसके अलावा एक्ट/कानून 2014 में भी है।  
 करके टाउन वैंडिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाये जो कि माननीय राज्यपाल  
 बैठाकर टाउन वैंडिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा सभी वैंडिंग के निरीक्षण/सर्वे  
 स्थान पर काम करने से वंचित नहीं किया जाये और उसके स्थान पर ही  
 टाउन वैंडिंग कमेटी जब तक बन न जाये जब तक किसी भी वैंडिंग को उसके  
 भीजेंद है।

3. एनडीएमसी इम्फोर्समेंट द्वारा 628 की मान्य लिस्ट में भी इनके नाम  
 एनडीएमसी इम्फोर्समेंट द्वारा दे रखा है।

2 3792 इलेजिबल लिस्ट का माननीय संप्रदाय कोर्ट में हल्फनामा भी  
 भरे थे जिसकी 100/- रु की रसीद भरे पास भीजेंद है।

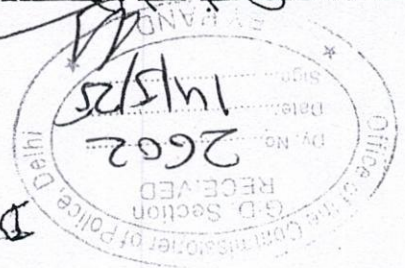
1. इन सभी वैंडिंगों ने सन 2007 में एन. डी. एम. सी. में तहबजायी फार्म  
 जो कलाथ हाउस (कपड़े का काम) करते हैं।

श्री बहादुर शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री बिलोकी शर्मा जी कनाट प्लस पालिका  
 बाजार गेट नम्बर-4 के पास कलाथ हाउस का बाजार लगाते हैं। लिस्ट नम्बर-  
 628 है। जो कि भेरा नं. 239 लिस्ट में नम्बर है। बहादुर शर्मा पदीय  
 शर्मा लिस्ट नम्बर-281 है। व भूमना लाल शर्मा 2984/2011 नीली का नाम  
 उसी तरह हमें भी बिठाया जाने के बारे में।

विषय :- जैसे NDMC ने कोर्ट के आदेश पर अन्य आदिमियों को बिठाया है

महोदय जी,

भारत सरकार नई दिल्ली  
 महामहिम VP House



DR/H/9

दिनांक :- 12.05.2025

श्री श्री  
 Vice-President's Secretariat  
 New Delhi - 110011  
 Date: 23/5/25  
 Received By: [Signature]  
 श्री श्री  
 1674

WZ PC-4511 वर्ष 2011 में हाई कोर्ट के आदेशानुसार हुआ है। इन को जब तक अलाटमेंट नहीं होती तब तक इन दोनों को प्रमादित व परेशान ना किया जाये। कोर्ट के आदेश का पालन किया जाये महीदय, NDMC चयरभेन पालिका बाजार कनाट लसे दिल्ली। WP 2452016 डबल ब्राच कोड 2016 है।

धन्यवाद

( 95752 2111 )  
 बहादुर शर्मा, प्लॉट नम्बर- 63,  
 शाली नम्बर 16, C-Block Shiv  
 चौक नवाली विहार बापरौला  
 West, दिल्ली -110043  
 प्रीबाइल नम्बर - 9871873647

Prima Minister's Office  
 राज गृहमंत्रालय  
 DARK SECTION  
 RECEIVED ON  
 Date 23/05/2025

Copy to-

1. VP House भारत सरकार दिल्ली।
2. श्रीमान प्रधान मंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली।
3. श्रीमान गृह मंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली।
4. श्रीमान उपराज्यपाल जी दिल्ली सरकार नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली सरकार नई दिल्ली।
6. श्रीमान कमिश्नर जी पुलिस हैडक्वार्टर नई दिल्ली।
7. श्रीमान चयरभेन जी एन.डी.एम.सी. नई दिल्ली।

श्रीमान प्रधान मंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली।  
 23 MAY 2025  
 (श्रीमान कक्षा)  
 प्रधान मंत्री कार्यालय

श्रीमान प्रधान मंत्री कार्यालय  
 MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
 नई दिल्ली / New Delhi  
 23 MAY 2025  
 श्रियत प्रमुख / Deputy Secretary  
 RECEIVED/C. R. SECTION  
 नई दिल्ली / North Block

8. The Chairman Public Grievance Commission,  
 M-Block, Vikas Bhawan, IP State, New Delhi -110010.

में मानता हूँ कि गरीबी, महागाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर भी हम 11 वर्षों में आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके हैं। अभी काम हो रहा है। परिवर्तन ओर दिखेगा।

# भादी सरकार समस्याओं को नियंत्रित करने में नहीं, समूल समाप्त करने में विश्वास करती है

लगातार तीसरी बार जीत के साथ केंद्र में आई नरेन्द्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। भाजपा की ओर से उपलब्धियों की लंबी सूची दिखाई जा रही है तो विपक्ष की ओर से यह जताने की कोशिश हो रही है कि अब सरकार दबाव में आ गई है। जतिवार गणना जैसे मुद्दों पर श्रेय लेने की भी कोशिश हो रही है। जबकि आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद से निपटने के मुद्दे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा व सरकार के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अश्विनी शहा ने तंज किया कि कांग्रेस के नेता इस भ्रम में हैं कि पूरा ब्रह्मांड उनकी वजह से चल रहा है। सच्चाई यह है कि पिछली सरकारों की मंशा और शासन का उनका दृष्टिकोण ही गलत था। दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक आशुतोष झा और सहायक संपादक नीलू रंजन से बातचीत में शाह कहते हैं कि पिछले 11 वर्षों के सुशासन के कारण ही देश में विश्वास पैदा हुआ है। हमने आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया है।



कांग्रेस नेता को लगता है कि पूरा ब्रह्मांड उनकी वजह से चल रहा है तो यह उनकी समस्या है। हमारी सरकार तो शुरू से गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के लिए काम कर रही है।

मनभेद को हम समाप्त कर पाए हैं। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। पहले दोनो को अलग-अलग बुलाया, फिर संयुक्त रूप से भी बुलाया है और अब राजनीतिक स्तर पर भी बात हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ समय में संभवता मिल जायेगी और पूर्ववत स्थिति बहाल होगी।

• जनगणना की घोषणा हो गई है। आंकड़े कब तक आये और परिशोधन की प्रक्रिया कब शुरू होगी ?  
- आंकड़े 2027 के अंत तक आने की उम्मीद है, वैसे 2027 के मध्य तक भी आ सकते हैं, क्योंकि इस बार हम तकनीक के आधार पर जनगणना कर रहे हैं। आप अपने परिवार की जानकारी खुद ही अपलोड कर सकते हैं, ऐसा एक सरल एप भारत की सभी भाषाओं में बनया है। अपलोड करने के बाद जनगणना कर्मियों आपके गांव में भी जा सकता है और दिल्ली में रहते हों, तो वहां भी आया। इसीलिए रिपोर्ट आने में जो पहले पांच छह साल लगते थे, इस बार पांच छह महीने में आ जाएगी। पहली बार एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक जनगणना हो रही है।

• तो 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले परिशोधन की भी संभावना बनती है ?  
- (हसते हुए) 2029 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ होगा।

• परिशोधन को लेकर दक्षिण के राज्य सवाल खड़े कर रहे हैं, आबादी के मुद्दे को लेकर।  
- स्टालिन अभी यह मुद्दा चुनाव के लिए ही उठा रहे हैं। उनको भी मालूम है कि 2026 के पहले परिशोधन नहीं होगा। ये मुद्दा शायद है, तो 2019 से अभी तक क्यों नहीं उठाया। 2025 में क्यों उठा रहे हो, क्योंकि 2026 में चुनाव आना है।

• सरकार में बहुत-बहुत बड़े फैसले होते हैं, लेकिन